केवल परिस्थितियां। कांस्टी-टेंट के तहत न्यायालयों की शक्तियां विशेषाधिकार रिट जारी करने तक ही सीमित नहीं हैं। अनुच्छेद 226 इस न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या अधिकार को "किसी भी दिशा, आदेश या लेखन" को जारी करने का अधिकार देता है। इस अदालत में ऐसे प्रशासनिक आदेशों के मामले में हस्तक्षेप करने की शक्ति है, जो कानून के अनिवार्य प्रावधानों की अवहेलना में या किसी अधिकार क्षेत्र के बिना किए गए हैं। तत्काल मामले में, सिंडिकेट का लगाया गया निर्णय उन शक्तियों का उल्लंघन था जो सीनेट और सरकार में क़ानून और वैधानिक नियमों के तहत बनते हैं।

याचिका सफल होने के योग्य है और इसलिए, अनुमति दी गई है। इसलिए, मैं विश्वविद्यालय के फैसले को समाप्त कर दूंगा, जो श्री करत सिंह के निलंबन या बर्खास्तगी के लिए अपनी सहमति देने के लिए गिरता है, प्रिंसिपल और आगे याचिकाकर्ता को उसे बहाल करने की आवश्यकता होगी। विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता को अपनी सेवा में प्रिंसिपल को वापस लेने की आवश्यकता होती है, जिसे खारिज कर दिया गया है, जो कि विनियम 11 और 12 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इस मामले में किसी भी अवलोकन के अनुसार, कॉम-प्लेन्स के संबंध में की गई इस मामले में कोई भी अवलोकन है। नियमों के साथ 11 और 12 को याचिकाकर्ता और प्रिंसिपल श्री करत सिंह के बीच विवाद का स्थगित करने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए, जिसे खारिज कर दिया गया था। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच, यदि कोई हो, तो मतभेदों के गुणों पर कोई सहायक नहीं है .. मैंने उसे एक विवाद में फंसाने के लिए उचित पार्टी नहीं माना है जो सीधे याचिकाकर्ता और विश्वविद्यालय के बीच है जिसमें अभ्यास सिंडिकेट द्वारा शक्तियों को अधिकार क्षेत्र और अवैधता की इच्छा के आधार पर लगाया गया है। मामले की परिस्थितियों में, मैं अपनी लागत वहन करने के लिए पार्टियों को छोड़ देता हूं।

K.S.K.

पुनरीक्षणीय सिविल

प्रेम चंद पंडित से पहले, जे भगत पंजू राम और अन्य, याचिकाकर्ता सिविल रिवीजन नंबर 4 1966

बनाम

राम लाल, प्रतिवादी

23 अक्टूबर, 1967

ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट (1949 का III) एस। 8-स्कोप ऑफ सूट

के लिए रेंट की वसूली के लिए दो बार भुगतान किया गया था, जो कि एस 8 द्वारा कवर किया गया था।Act भगत पंजू राम, आदि ई। राम लाल (पंडित, जे।)

आयोजित, पूर्वी पंजाब अर्बन रेंट प्रतिबंध अधिनियम, 1949 की धारा 8, मकान मालिक से किरायेदार द्वारा उन रकमों की वसूली से संबंधित है, जो अधिनियम के प्रावधानों के कारण उनसे अपरिचित थे। पूर्ववर्ती दो धारा 6 और 7 में उन लोगों का उल्लेख किया गया है और यदि इस तरह के रकम को मकान मालिक से किरायेदार द्वारा पुनर्प्राप्त करने की मांग की जाती है, तो धारा 8 के प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा। लेकिन अगर मकान मालिक ने किरायेदार से दो बार की अवधि के लिए किराया बरामद किया है, तो किरायेदार द्वारा किराए के खाते में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए मुकदमा अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के भीतर नहीं होगा। इस तरह के सूट को सीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 120 या सीमा अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 113 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत याचिका, 1908 श्री देव राज सैनी के आदेश के संशोधन के लिए, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ, रोहटक, 17 दिसंबर, 1965 को, श्री प्रेम कुमार जैन, सब को उलट देते हैं। -दज, ।।। क्लास, रोहटक, दिनांक 4 अप्रैल, 1965 को रु। 660 दोनों अदालतों की लागत के साथ प्रतिवादियों के खिलाफ वादी के पक्ष में।

एच। एल। सरीन, याचिकाकर्ताओं के लिए बहल सिंह मलिक, अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता।

पी। सी। जैन, वकील, प्रतिवादी के लिए।

प्रलय

पंडित, जे। कुछ परिसर, रोहटक शहर में स्थित, इसके मालिक भगत पंजा राम ने राम लाल को रुपये के मासिक किराए पर पट्टे पर दिया था। 110. 1 अगस्त, 1961 को, राम लाल ने मकान मालिक को भुगतान किया। 5 जुलाई, 1961 से 5 जनवरी, 1962 की अवधि के लिए छह महीने के लिए किराए के खाते में 660। 16 जनवरी, 1963 को, भगत पंजू राम ने पूर्वी पंजाब अर्बन रेंट प्रतिबंध अधिनियम की धारा 13 के तहत एक आवेदन दायर किया (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) 6 जुलाई, 1961 से 16 जनवरी, 1963 तक किराए के बकाया राशि के भुगतान के गैर-भुगतान के आधार पर राम लाल के खिलाफ। - मेंट, 1 अगस्त 1961 को, 5 जुलाई, 1961 से 5 जनवरी, 1962 तक छह महीने के लिए, लेकिन इस बात से डर है कि उन्हें बाहर निकाल दिया जा सकता है, वह, इस बेदखल याचिका की सुनवाई

की पहली तारीख को, अर्थात्, 28 जनवरी, 28 जनवरी, 1963, भुगतान रुपये। 2,205 जिसने 6 जुलाई, 1961 से 16 जनवरी, 1963 तक पूरी अवधि के लिए किराए को कवर किया। उक्त भुगतान के बाद, बेदखल याचिका को खारिज कर दिया गया। 21 मार्च, 1964 को राम लाल ने रु। 720, रु। 5 जुलाई, 1961 से 5 जनवरी तक किराए के खाते में 660, 1962 जो प्रतिवादी द्वारा दो बार बरामद किया गया था, और रु। 60 जो 1 अगस्त, 1961 को अन्य खर्चों के कारण प्रतिवादी को उनके द्वारा भुगतान किया गया था।

मुकदमा प्रतिवादी द्वारा कई दलीलों पर लड़ा गया था, लेकिन इस संशोधन याचिका में, हम केवल उनमें से एक के साथ चिंतित हैं, अर्थात्, सूट को सीमा से रोक दिया गया था। ट्रायल जज ने प्रतिवादी के पक्ष में सीमा के मुद्दे का फैसला किया और सूट को खारिज कर दिया। उनके अनुसार, 28 जनवरी, 1963 को अधिनियम की धारा 8 के तहत किए गए अतिरिक्त राशि के भुगतान की तारीख से छह महीने के भीतर सूट दायर किया जा सकता था। 21 मार्च, 1964 को इस सूट को इस प्रकार स्पष्ट रूप से समय के साथ रोक दिया गया था। रिलायंस को सीखा न्यायाधीश द्वारा फालशॉ, सी। जे। में धनी राम और अन्य वी। पीटी के फैसले पर रखा गया था। ग़सिता राम (1), जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि जहां एक किरायेदार ने अवैध रूप से इस तरह के किराए से कटौती या अलग-अलग एसी-टियोन द्वारा भुगतान किए गए किराए को पुनर्प्राप्त करने की मांग की थी, उसे भुगतान की तारीख से छह महीने के भीतर ऐसा करना चाहिए।

अपील में सीखे गए वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, रोहटक ने, सीमा के सवाल पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट दिया और रुपये के लिए मुकदमा दायर किया। राम लाल के पक्ष में 660। रु। 60 पारित किया गया था, इस राशि का भुगतान राम लाल द्वारा किराए के बकाया के रूप में नहीं किया गया था। उनकी खोज यह थी कि अधिनियम की धारा 8 ने लागू किया जब एक राशि जो भुगतान की गई थी, वह किराए पर प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों के कारण अचूक थी। इस तरह की रकम, सीखा न्यायाधीश के अनुसार, अधिनियम की धारा 6 और 7 में दी गई थी। पूर्व भेजे गए सूट उस तरह की राशि की वसूली के लिए एक नहीं था। मुकदमा किराए के दोहरे भुगतान के कारण भुगतान किए गए धन की वसूली के लिए था। सीखा न्यायाधीश के अनुसार धनी राम का मामला तथ्यों पर अलग था। वहां, परिसर का किराया रु। 13/12 प्रति मेन्सेम। हालांकि, मकान मालिक को रुपये की दर से एहसास हुआ था। 16/12 प्रति माह। रुपये का किराया। 3 हर महीने इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपरिवर्तनीय था। इसलिए, सीखे हुए न्यायाधीश के लिए, ओवर-पेल्ड किराए की वसूली के लिए सूट इसके भुगतान की तारीख से

छह महीने के भीतर दायर किया जाना था। उन्होंने आगे देखा कि पूर्व भेजे गए प्रकृति के एक सूट के लिए सीमा की अवधि, हालांकि, सीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 62 में दी गई थी। चूंकि सूट भुगतान की तारीख के तीन साल के भीतर दायर किया गया था। 1 अगस्त, 1961, यह स्पष्ट रूप से सीमा के भीतर था। इस फैसले के खिलाफ भगत पंजू राम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत इस अदालत में आए हैं।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस अदालत में संशोधन याचिका की पेंडेंसी के दौरान, भगत पंजा राम की मृत्यु हो गई और उनके कानूनी रिप्रेजेंटेशन को उनके स्थान पर रिकॉर्ड पर लाया गया था।

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील द्वारा उठाए गए एकमात्र विवाद यह था कि सीखा वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने कानून में जोर दिया था कि मुकदमा सीमा के भीतर था। सीखे हुए वकील के अनुसार, धारा 8 ने तात्कालिक मामले के तथ्यों पर लागू किया और ढनी राम के मामले में फाल्शॉ, सी.जे. के फैसले के कारण, सूट को समय के साथ रोक दिया जाना चाहिए था।

अधिनियम की धारा 8 का प्रासंगिक भाग पढ़ता है-

"(1) जहां कोई भी राशि है, चाहे इस अधिनियम के कॉम से पहले या बाद में, इस अधिनियम के प्रावधानों के कारण यह भुगतान किया गया हो, जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के कारण, इस तरह की राशि, छह महीने की अवधि के भीतर किसी भी समय, इस तरह की राशि होगी। भुगतान की तारीख, या इस अधिनियम के शुरू होने से पहले किए गए भुगतान के मामले में, इसके शुरू होने के छह महीने बाद, किरायेदार द्वारा पुनर्प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, जिसके द्वारा इसका भुगतान किया गया था, या मकान मालिक से उसका कानूनी प्रतिनिधि जो प्राप्त हुआ था। भुगतान या उसका कानूनी प्रतिनिधित्व-tive, और बिना किसी अन्य विधि के पूर्वाग्रह के बिना फिर से ऐसे किरायेदार द्वारा ऐसे किरायेदार द्वारा कटौती की जा सकती है, जो ऐसे छह महीनों के भीतर किसी भी किराए से देय हो सकता है।

(२)

इस प्रावधान के एक सादे पढ़ने से पता चलेगा कि यह मकान मालिक से किरायेदार द्वारा उन रकमों की वसूली से संबंधित है, जो अधिनियम के प्रावधानों के कारण उनसे अपूरणीय था। पूर्ववर्ती दो खंड 6 और 7. धारा 6 में उन लोगों का उल्लेख किया गया है जो मकान मालिक किरायेदार से उचित किराए से अधिक में कुछ भी दावा नहीं कर सकते हैं। धारा 7 का कहना है कि कोई भी मकान मालिक,

किसी भी इमारत या किराए की भूमि के किरायेदारी के अनुदान, नवीकरण या निरंतरता को ध्यान में रखते हुए, किराए के अलावा किसी भी जुर्माना, प्रीमियम या किसी भी अन्य राशि के भुगतान की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, यदि मकान मालिक ने किरायेदार से कुछ भी नहीं बरामद किया है, तो खंड 6 और 7 के प्रावधानों के बारे में बताया गया है, उन रकमों को कहा जा सकता है इस अधिनियम के प्रावधानों के कारण जमींदार द्वारा अपूरणीय हो। यदि इस तरह के रकम को मकान मालिक से किरायेदार द्वारा पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, तो धारा 8 के प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा। तत्काल मामले में, हालांकि, माना जाता है कि मकान मालिक को इसी अवधि के लिए किराए का दोहरा भुगतान मिला था। उन्होंने एक बेदखल-मानसिक आवेदन दायर किया और एक लिखित दावा करके कि उन्हें 5 जुलाई, 1961 से 5 जनवरी की अवधि के लिए कोई किराया नहीं दिया गया था; 1962, सह-गेरो द्वारा सुनवाई की पहली तारीख को किरायेदार से वही मिला, जैसे कि, क्योंकि अन्यथा किरायेदार को परिसर से बाहर कर दिया गया हो सकता है। इस तरह की राशि की वसूली, मेरे विचार में, अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के भीतर नहीं आती है। तथ्य की बात के रूप में, किराए पर प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों का मकान मालिक से इस तरह की राशि की वसूली से कोई लेना -देना नहीं है, क्योंकि यह राशि अवैध रूप से उनके द्वारा किरायेदार से गलत प्रतिनिधित्व करके पुनर्प्राप्त की गई थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा भरोसा किया गया ढनी राम का मामला तथ्यों पर अलग है। उस अधिकार में, यह रिपोर्ट से प्रकट होता है कि सूट में परिसर का उचित किराया रु। 13-12-0 प्रति मेन्सेम। हालांकि, जमींदारों ने इसे रु। की दर से पुनर्प्राप्त किया। 16-12-0 प्रति मेन्सेम। चूंकि जमींदारों ने उचित किराए से अधिक किराया प्राप्त किया था, इसलिए, यह था कि सीखा मुख्य न्यायाधीश ने उस मामले में अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों को लागू किया। वरिष्ठ अधीनस्थ- नैट न्यायाधीश इस प्रकार सही थे कि अधिनियम की धारा 8 के पास वर्तमान मामले के लिए कोई आवेदन नहीं था। उनकी खोज, हालांकि, यह सूट भारतीय सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 62 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। 1908, मेरे विचार में, सही नहीं है, यह लेख मनी पे के लिए सूट पर लागू होता है- प्रतिवादी द्वारा वादी द्वारा पूर्व द्वारा प्राप्त धन के लिए वादी के लिए सक्षम। तात्कालिक मामले में प्रतिवादी को वादी के उपयोग के लिए कभी कोई पैसा नहीं मिला। वास्तव में, वादी के अनुसार, प्रतिवादी, अवैध रूप से और जबरदस्ती द्वारा वादी से पैसे मिल गए थे। तब यह सुझाव दिया गया था कि अनुच्छेद 96 लागू होगा। लेकिन, मेरी राय में, उस लेख में भी इस मामले का कोई आवेदन नहीं है, क्योंकि यह उन सूटों को नियंत्रित करता है जो गलती के आधार पर राहत के लिए दायर किए जाते हैं। यह वादी का मामला नहीं है कि उसने कुछ गलती के कारण प्रतिवादी को विवाद में राशि का

भुगतान किया था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, उन्हें इस राशि को बचाव पक्ष को जबरदस्ती के तहत भुगतान करना पड़ा, क्योंकि बाद में किराए के नियंत्रक से पहले अपने बेदखल के लिए एक मुकदमा दायर किया था और अगर उन्होंने सुनवाई के पहले दिन इस राशि को नहीं दिया था, उसे परिसर से बेदखल कर दिया गया हो सकता है। मुझे इस बात का विचार है कि इस मामले की परिस्थितियों में, लागू लेख एक अवशिष्ट एक होगा, अर्थात्, अनुच्छेद 120 जो सूट से संबंधित है जिसके लिए कोई अवधि नहीं है सीमा की पहली अनुसूची में कहीं और प्रदान की जाती है। इस लेख में सीमा उस समय से छह साल है जब वादी के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार और वह 28 जनवरी, 1963 का होगा, जब प्रतिवादी को दोहरा भुगतान किया गया था। 21 मार्च, 1964 को लाया गया सूट, इसलिए, सीमा के भीतर अच्छी तरह से था।

मैंने जो कहा है, उसे देखते हुए, यह संशोधन याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। वहाँ होगा। हालांकि, इस अदालत में लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

बीआर.टी.

चुनाव याचिका

ए। एन। ग्रोवर से पहले, जे। पारस राम, -पुटिशनर

शिव चंद और अन्य, उत्तरदाता

1967 की चुनाव याचिका संख्या 14।

24 अक्टूबर, 1967

भारत का संविधान (1950) कला। 341-सवस्थता (अनुसूचित जातियां) ऑर्डर (1950) पार्ट एक्स (पंजाब), आइटम 9-मोचिस-चाहे एक अनुसूचित जाति के रूप में चामर्स-सेन्सस एक्ट (1948 का xxxvii) एस। 15-रेफरेंस टू जनगणना रिपोर्ट-क्या।

हेल्ड, हालांकि, चामर्स और मोचिस, जो कि टैन किए गए चमड़े में श्रमिक थे, मूल रूप से एक ही जाति के थे या सभी घटनाओं में निकटता से जुड़े थे, मोचिस एक अलग जाति या उप-जाति के रूप में विकसित हुए थे, जो कि वियर्स के दौरान थे। मोचिस चामर्स के समान जाति के नहीं हैं और संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950 के भाग एक्स (पंजाब) के आइटम नंबर 9 में शामिल नहीं हैं। इसलिए,

इसलिए, एक अनुसूचित जाति नहीं है।

आयोजित, जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जनजातियों, जातियों या धर्मों से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक या सांख्यिकीय या सिरेलर जानकारी के संदर्भ में नहीं है और यह केवल किसी भी का निरीक्षण करता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा